(c) what criteria the Ministry has followed in selecting the workers representatives on both the Boards?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P. "A. SANGMA): la) to (c) Yes, Sir; the secretariat of the Wage Boards has been doing preparatory work since their constitution. A meeting of the Wage Boards has also been convened on 3-4-1995. Workers representatives on both the Boards have been selected on the basis of the recommondations of the Working Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees Organisations.

मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी

*91. श्री ईश दत्त यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक प्रतिष्ठानों में मजदूरों को न्यूनतम एवं निर्धारित मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है अथवा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में कोई विचार-विमर्श किया है अथवा ऐसा करने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने नियमों का उल्लघंन करने वाले ऐसे प्रतिष्ठानों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन किया जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की है ?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों ही अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण, संशोधन और प्रवर्तन के लिये समुचित सरकारें हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के उल्लंघन के बारे में शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं । सरकार ने 29-30 सितम्बर, 1994 को भुवनेश्वर में पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, 4 अक्तूबर, 1994 को त्रिवेन्द्रम में दक्षिणी क्षेत्र और 25 अक्तूबर, 1994 को जयपुर में मध्य तथा उत्तरी क्षेत्रों के क्षेत्रीय श्रम मंत्रियों के सम्मेलन आयोजित किये हैं । इन सम्मेलनों में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों के साथ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया गया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रवर्त्तन को सुदृढ़ बनाने के लिये अनेक निर्णय लिये गये हैं । इनमें प्रिंट मीडिया, रेडियो प्रसारण, इलैक्ट्रानिक मीडिया, होर्डिंग आदि के माध्यम से अधिनियम के उपबंधों का व्यापक प्रसार, अधिनियम के उल्लंघन के लिये शास्ति में बढ़ोतरी, दावा प्राधिकारियों की नियुक्ति के लिये पात्रता मानदंड का प्रसार, दावा निपटान पद्धतियों को सरल बनाना आदि शामिल है । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को अन्य सहयोगी विभागों की सहायता लेकर, निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि कर के, और जिला स्तरीय निगरानी समितियां आदि गठित करके प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ किये जाने की भी सलाह दी गयी है ।

Production of rubber

*92. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the total production of rubber during the last three years in the country, state-wise;

(b) the total requirement of rubber during the currnt year in the country, industry-wise;

(c) whether the Government have any proposal to import natural rubber during the current year; and

(d) if so, the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) The total *pro-*